

राइट-टू-रपियर

प्रलिस के लयि:

राइट-टू-रपियर, ई-कचरा, मरमत के अधिकार पर समति

मेन्स के लयि:

ई-कचरे का पर्यावरणीय प्रभाव, मरमत के अधिकार का दायरा, बढ़ती एकाधिकार वाली कंपनयिों का मुकाबला कैसे करें, सरकार की पहल

चर्चा में क्यो?

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के वभाग ने घोषणा की क उसने 'राइट-टू-रपियर' पर व्यापक ढाँचा वकिसति करने के लयि अतरिकित सचवि नधि खरे की अधयकषता में समति का गठन कया है।

राइट-टू-रपियर:

परचिय:

- 'राइट-टू-रपियर' एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भति करता है, जसिका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरमत करना और उन्हें संशोधति करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के नरिमाता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो यह स्वाभाविक है क उनके पास उस वस्तु पर पूरण स्वामतिव हो जाता है, जसिके लयि उपभोक्ताओं को मरमत हेतु नरिमाताओं द्वारा आसानी से और उचति लागत पर उत्पाद की मरमत और संशोधन करने में सकषम होना चाहयि।
- 'राइट-टू-रपियर' का वचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ 'मोटर वहीकल ओनर्स राइट-टू-रपियर एक्ट, 2012' कसिी भी व्यक्तिको वाहनों की मरमत करने में सकषम बनाने के लयि वाहन नरिमाताओं के लयि सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करना अनविर्य बनाता है।

प्रस्तावति ढाँचा:

- इस नयामक ढाँचे के तहत नरिमाताओं के लयि अपने उत्पाद वविरण को ग्राहकों के साथ साझा करना अनविर्य होगा ताकवि मूल नरिमाताओं पर नरिभर रहने के बजाय स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा उनकी मरमत करा सकें।
- कानून का उद्देश्य मूल उपकरण नरिमाताओं (OEMs) और तीसरे पक्ष के खरीदारों तथा वकिरेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापति करने में मदद करना है, साथ ही इस प्रकार नए रोजगार का सृजन भी करना है।

वैश्वकि स्थति:

- अमेरिका, बरटिन और यूरोपीय संघ सहति दुनया भर के कई देशों में मरमत के अधिकार को मानयता दी गई है।
- अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग ने नरिमाताओं को अनुचति प्रतसिपर्द्धा-वरिधी प्रथाओं को दूर करने का नरिदेश दया है और उन्हें यह सुनिश्चति करने के लयि कहा है क उपभोक्ता स्वयं या कसिी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा मरमत करा सकें।

संभावति लाभ:

- यह छोटी मरमत की दुकानों के लयि व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हसिसा है।
- यह इलेक्ट्रिक कचरे (e-waste) के वशाल ढेर को कम करने में मदद करेगा।
- इससे उपभोक्ताओं का पैसा बचेगा।
- यह उपकरणों के जीवन काल, रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चकरण और अपशषिट प्रबंधन में सुधार करके चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।

कार्यानवयन हेतु प्रस्तावति कषेत्तर:

- कृषा उपकरण
- मोबाइल फोन/टैबलेट

- उपभोक्ता के लिये टिकाऊ वस्तुएँ
- ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण

राइट-टू-रपियर की आवश्यकता:

- आमतौर पर नरिमाता अपने डिज़ाइन सहित स्पेयर पार्ट्स पर मालिकाना नियंत्रण बनाए रखते हैं, रपियर प्रक्रियाओं पर इस तरह का एकाधिकार ग्राहक के "चुनने के अधिकार" का उल्लंघन करता है।
- कई उत्पादों के वारंटी कार्ड में उल्लेख किया जाता है कि गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों रपियर कराने की स्थिति में ग्राहक वारंटी लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- कंपनियाँ मैनुअल के प्रकाशन से भी बचती हैं जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से रपियर करने में मदद कर सकती हैं।
- तकनीकी सेवा/उत्पाद कंपनियाँ मैनुअल, स्कीमैटिक्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिये पूर्ण ज्ञान एवं पहुँच प्रदान नहीं करती हैं।
- नरिमाता "नियोजित अप्रचलन" की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
 - यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी भी गैजेट का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वह एक विशेष समय तक ही रहता है और उस विशेष अवधि के बाद उसे अनविरय रूप से बदलना पड़ता है।
 - एक उत्पाद जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत आता है अर्थात।
 - कृत्रिम रूप से सीमित उपयोगी जीवन वाले उत्पाद को डिज़ाइन करना
 - न केवल ई-कचरा बन जाता है बल्कि उपभोक्ताओं को किसी मरम्मत के अभाव में नए उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके।
 - एक उत्पाद जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या नियोजित अप्रचलन के तहत आता है यानी कृत्रिम रूप से सीमित उजीवनकाल के लिये उपयोगी उत्पाद को डिज़ाइन करना न केवल ई-कचरा को बढ़ाएगा बल्कि उपभोक्ताओं को रपियर करने की अपेक्षा नए उत्पाद खरीदने के लिये मजबूर करेगा।
- भारत ने हाल ही में LIFE आंदोलन (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) की अवधारणा शुरू की है।
 - इसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्रचकरण की अवधारणा शामिल है।
 - राइट-टू-रपियर, लाइफ मूवमेंट के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

आगे की राह

- नैदानिक उपकरणों सहित सेवा संबंधी उपकरणों को व्यक्तियों सहित तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराए जाने चाहिये ताकि भामूली गड़बड़ियों के मामले में उत्पाद की रपियरिंग की जा सके।
 - 'राइट-टू-रपियर' कानून भारत जैसे देश में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है, जहाँ सेवा नेटवर्क अक्सर असमान (Spotty) होते हैं और अधिकृत कार्यशालाएँ कम होने के साथ ही दूर के इलाकों में होती हैं।
 - भारत में अनौपचारिक रपियरिंग क्षेत्र की स्थिति भिन्न है।
 - लेकिन अगर इस तरह के कानून को अपनाया जाता है तो मरम्मत और रखरखाव सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।

स्रोत: द हद्दि